No. 1/19/2009-1PR(FD)

From

Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana,
Finance Department.

To

1. All the Administrative Secretaries.
2. All the Head of Departments of State of Haryana.
3. The Commissioners, Ambala, Hisar, Rohtak and Gurgaon Division.
4. All the Dy. Commissioners of Haryana.
5. All the SDO (C) of Haryana.

Dated, Chandigarh the 07th November, 2014

Subject: **Regarding amendment in proviso to Rule 7 (1) (A) of HCS (RP) Rules, 2008 and proviso to Rule 18 (A) of HCS (ACP) Rules, 2008.**

******

Please find enclosed a copy of notification dated 04-11-2014, on the subject noted above for further necessary action.

Joint Secretary Finance (PR)
for Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana,
Finance Department

Endst. No. 1/19/2009-1PR (FD), dated, Chandigarh the 07-11-2014

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

(i) Advocate General, Haryana.
(ii) Principal Accountant General (A&E/ Audit), Haryana.
(iii) Haryana Bureau of Public Enterprises.

Joint Secretary Finance (PR)
for Addl. Chief Secretary to Govt. Haryana,
Finance Department

INTERNAL CIRCULATIONS

(i) All the Officers/Joint, Deputy, Under Secretaries/Superintendents of F.D.
(ii) In-charge, Computer Cell (F.D.).

Regd. No. CHD/0093/2012–2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 4, 2014 (KARTIKA 13, 1936 SAKA)

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 04 नवम्बर, 2014

संख्या 1/19/2009–1पी.आर. (एफ.डी.).– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जनवरी, 2006 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में, नियम 7 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उप–खण्ड (iii) रखा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तुक–

(I) जहां, वेतन नियत करने में, ऐसे सरकारी कर्मचारियों का, जो वर्तमान स्केल में दो या अधिक क्रमवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वेतन एकत्रित कर लिया जाता है, अर्थात वेतन बैंड में उसी प्रक्रम में पुनरीक्षित वेतन ढांचे में नियत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तब इस प्रकार एकत्रित प्रत्येक दो पक्रमों हेतु, एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा ताकि पुनरीक्षित चालू वेतन बैंड में दो से अधिक बंचिंग को रोका जा सके। प्रयोजन हेतु, वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर संगणित की जाएगी। आगे, बंचिंग के कारण वेतन वृद्धि का लाभ ऐसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जहां पद का पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान इन नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग ख में, अनुभाग II में, खाना 4 के नीचे यथानिर्दिष्ट उपान्तरित किया गया है। ग्रेड वेतन एलीवेट बंचिंग हेतु वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(II) वेतन बैंड पी बी–4 में उच्चतर प्रशासकीय ग्रेड (एच.ए.जी.) में वेतनमानों के मामले में, बंचिंग के कारण वेतनवृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों में सभी प्रक्रमों के मद्दे दिया जाएगा। आगे, बंचिंग के कारण वेतन वृद्धि का लाभ ऐसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जहां पद का पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान इन नियमों की प्रथम अनुसूची के भाग ख में, अनुभाग II में, खाना 4 के नीचे यथानिर्दिष्ट उपान्तरित किया गया है;

(III) यदि यथा उपरोक्त वेतन बढ़ाते हुए, सरकारी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित वेतन बैंड/ वेतनमान (जहां लागू हो) में प्रक्रम में नियत किया जाता है जो पुनरीक्षित वेतन बैंड में प्रक्रम से उच्चतर है जिस पर सरकारी कर्मचारी का वेतन, जो उसी वर्तमान स्केल में अगले उच्चतर प्रक्रम अथवा प्रक्रमों पर ले रहा था, नियत किया जाता है, तो पिछले का वेतन भी केवल उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जहां तक यह उस पूर्ववर्ती से कम पड़ता है।

(iii) वेतन बैंड में वेतन उपरोक्त रीति में निर्धारित किया जाएगा। वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त वर्तमान स्केल के समरूप ग्रेड वेतन भुगतानयोग्य होगा।"।

राजन गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2014

No. 1/19/2009-1PR(FD).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, namely:—

1. (i) These rules may be called the Haryana Civil Services (Revised Pay) (Amendment) Rules, 2014.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. In the Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, in rule 7, in sub rule '1', in clause (A), for the existing proviso, the following proviso and the clause (iii) shall be inserted and substituted, namely:—

"Provided that :—

(I) Where, in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. Further, the benefit of increment due to bunching shall not be given in cases where the pre-revised pay scale of the post has been modified as indicated under column 4, in Section-II, in Part B of First Schedule of these rules. Grade Pay would not be taken into account for the purpose of granting increment to alleviate bunching.

(II) In the case of pay scales in higher administrative grade (HAG) in the pay band PB-4, benefit of increments due to bunching shall be given taking into account all the stages in different pay scales in this grade. Further, the benefit of increment due to bunching shall not be given in cases where the pre-revised pay scale of the post has been modified as indicated under column 4, in Section II, in Part B of First Schedule of these rules;

(III) If by stepping up of the pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised pay band/ pay scale (where applicable) which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a Government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of then that of the former. The pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable".

(iii) The pay in the pay band will be determined in the above manner. In addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale will be payable.

RAJAN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Finance Department.

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 04 नवम्बर, 2014

संख्या 1/19/2009–1पी.आर. (एफ.डी.).–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

(2) ये जनवरी, 2006 के प्रथम दिन से लागू हुए समझे जाएंगे।

2. हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्रगति) नियम, 2008 में, नियम 18 में, खण्ड (क) में, उप–खण्ड (ख) में, मद (ii) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तुक–

(I) जहां, वेतन नियत करने में, ऐसे सरकारी कर्मचारियों का, जो वर्तमान स्केल में दो या अधिक क्रमवर्ती प्रक्रमों पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वेतन एकत्रित कर लिया जाता है, अर्थात वेतन बैंड में उसी प्रक्रम में पुनरीक्षित ए.सी.पी. वेतन ढांचे में नियत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तब इस प्रकार एकत्रित प्रत्येक दो प्रक्रमों हेतु, एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा ताकि पुनरीक्षित ए.सी.पी. चालू वेतन बैंड में दो से अधिक बंचिंग को रोका जा सके। प्रयोजन हेतु, वेतनवृद्धि ए.सी.पी. वेतन बैंड में वेतन पर संगणित की जाएगी। आगे, बंचिंग के कारण वेतन वृद्धि का लाभ ऐसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जहां पद का पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान इन नियमों की अनुसूची 1, भाग I के खाना 4 में यथानिर्दिष्ट उपान्तरित किया गया है। ग्रेड वेतन एलीवेट बंचिंग हेतु वेतनवृद्धि प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा;

(II) वेतन बैंड पी बी–4 में उच्चतर प्रशासकीय ग्रेड (एच.ए.जी.) में वेतनमानों के मामले में, बंचिंग के कारण वेतनवृद्धियों का लाभ इस ग्रेड में विभिन्न वेतनमानों में सभी प्रक्रमों के मद्दे दिया जाएगा। आगे, बंचिंग के कारण वेतन वृद्धि का लाभ ऐसे मामलों में नहीं दिया जाएगा जहां पद का पूर्व पुनरीक्षित वेतन मान इन नियमों की अनुसूची 1, भाग I के खाना 4 में यथानिर्दिष्ट उपान्तरित किया गया है;

(III) यदि यथा उपरोक्त वेतन बढ़ाते हुए, सरकारी कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षित ए.सी.पी. वेतन बैंड/वेतनमान (जहां लागू हो) में प्रक्रम में नियत किया जाता है जो पुनरीक्षित ए.सी.पी. वेतन बैंड में प्रक्रम से उच्चतर है जिस पर सरकारी कर्मचारी का वेतन, जो उसी वर्तमान स्केल में अगले उच्चतर प्रक्रम अथवा प्रक्रमों पर ले रहा था, नियत किया जाता है, तो पिछले का वेतन भी केवल उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जहां तक यह उस पूर्ववर्ती से कम पड़ता है।

राजन गुप्ता,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 4th November, 2014

No. 1/19/2009-1PR(FD).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2008, namely:-

1. (i) These rules may be called the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) (Amendment) Rules, 2014.

(ii) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2006.

2. In the Haryana Civil Services (Assured Career Progression) Rules, 2008, in rule 18, in clause (A), in sub rule (b), in item (ii) for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that.—

(I) where, in the fixation of pay, the pay of Government servants drawing pay at two or more consecutive stages in an present scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised ACP pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running ACP pay bands. Further, the benefit of increment due to bunching shall not be given in cases where the pre-revised pay scale of the post has been modified as indicated in column 4 of Schedule 1, Part I of these rules. Grade Pay would not be taken into account for the purpose of granting increments to alleviate bunching;

(II) in the case of pay scales in higher administrative grade (HAG) in the pay band PB-4, benefit of increments due to bunching shall be given taking into account all the stages in different pay scales in this grade. Further, the benefit of increments due to bunching shall not be given in case where pre revised pay scale of the post has been modified as indicated in column 4 of Schedule 1, Part I of these rules;

(III) if by stepping up of the pay as above, the pay of a Government servant gets fixed at a stage in the revised ACP pay band/ pay structure (where applicable) which is higher than the stage in the revised ACP pay band at which the pay of a Government servant who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same present scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former".

RAJAN GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government,
Haryana, Finance Department.

52760—C.S.—H.G.P., Chd.